



गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवों गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16

अंक : 072

दि. 11.07.2026,

शनिवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

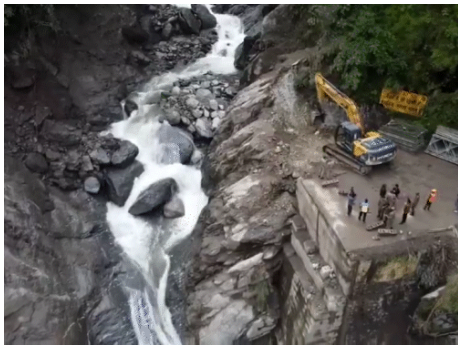
देश के भूजल पर बढ़ता प्रदूषण का खतरा, 22 प्रतिशत नमूनों में तय सीमा से अधिक मिला नाइट्रेट

नई दिल्ली : देश में भूजल की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रस्तुत ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के 22.02 प्रतिशत भूजल नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है। जित्ता की बात यह है कि पिछले तीन वर्षों से इस समस्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वर्ष 2023 में जहां 19.8 प्रतिशत नमूनों में नाइट्रेट की अधिकता पाई गई थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 20.7 प्रतिशत और 2025 में 22.02 प्रतिशत तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्राथमिक कदम नहीं उठाए गए तो भूजल प्रदूषण भविष्य में

पर्यावरण और जल सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2025 में मानसून से पहले देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 23,610 भूजल नमूने एकत्र कर उनकी वैज्ञानिक जांच की गई। इन नमूनों में नाइट्रेट के अलावा फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, यूरेनियम तथा अन्य रासायनिक तत्वों की भी जांच की गई। विश्लेषण में पाया गया कि बड़ी संख्या में स्थानों पर नाइट्रेट का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और



पंजाब उन राज्यों में शामिल हैं जहां राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक क्षेत्रों के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित सीमा से ऊपर दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, अनुपचारित सीवेज,

सेवन से अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आशंका भी बढ़ सकती है।

रिपोर्ट में राजधानी दिल्ली की स्थिति को भी चिंताजनक बताया गया है। वर्ष 2025 में दिल्ली के 208 स्थानों से लिए गए भूजल नमूनों में से 72 नमूनों, यानी 34.62 प्रतिशत, में नाइट्रेट का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। इसके विपरीत वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 20.9 प्रतिशत था। एक वर्ष के भीतर हुई इस उल्लेखनीय वृद्धि ने राजधानी में भूजल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को अवसर प्रकट कर और अधिक गंभीर बना दिया है।

झारखंड में भी नाइट्रेट प्रदूषण में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में राज्य के 561 स्थानों से

लिए गए नमूनों में से 161 नमूनों, अर्थात् लगभग 25 प्रतिशत, में नाइट्रेट की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई। जबकि वर्ष 2024 में यह आंकड़ा केवल 5.9 प्रतिशत था। रिपोर्ट में दर्ज यह वृद्धि राज्य में भूजल गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता को और संकेत करती है।

नाइट्रेट के अलावा रिपोर्ट में फ्लोराइड और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (ईसी) के बढ़े हुए स्तर पर भी चिंता व्यक्त की गई है। वर्ष 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार, देश के 9.23 प्रतिशत भूजल नमूनों में फ्लोराइड और 7.25 प्रतिशत नमूनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। विशेषज्ञों के अनुसार, फ्लोराइड की अधिक मात्रा लंबे समय

तक सेवन करने से दांतों और हड्डियों में संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जबकि अत्यधिक नलेजिबल कॉन्डिक्टिविटी पानी में घुले लवणों का अधिकांश का संकेत देती है, जो जल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में भूजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी, सांस्थनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, औद्योगिक अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबंधन, सीवेज उपचार व्यवस्था को मजबूत करने और वर्षा जल संचयन जैसी पहल को व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही जिन क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण अधिक पाया गया है, वहां स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध

कराने तथा जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भूजल कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। विशेष भारत में पेयजल और सिंचाई पर प्रमुख स्रोत है। ऐसे में उसकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट केवल पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और जन सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौती थी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रदूषण की वर्तमान प्रवृत्ति पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और अधिक चिन्तित हो सका है। इसलिए वैज्ञानिक निगरानी, जनजागरूकता और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से भूजल संसाधनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक होगा।

बांग्लादेश वापसी की तैयारी में अवामी लीग, शेख हसीना के साथ लौटने की घोषणा; नेताओं की रिहाई को बताया पहली प्राथमिकता

नई दिल्ली : बांग्लादेश की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के वरिष्ठ नेता मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि वह उन नेताओं में शामिल होंगे जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकता देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियों को फिर से सामान्य बनाना और हिरासत में बंद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को कानूनी राहत दिलाना है।



से आगे बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की भी मांग की, ताकि पार्टी सामान्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। मोहिबुल चौधरी के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस संबंध में अपनी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को विस्थापित है कि बांग्लादेश की न्यायपालिका, पुलिस, सेना और सीमा सुरक्षा बल संविधान और कानून के अनुरूप नियम्य तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी संस्थाओं की नियम्य भूमिका ही राजनीतिक स्थिरता और जनविश्वास को मजबूत कर सकती है। चौधरी ने आगे कहा कि पार्टी नेतृत्व देश लौटकर कानून का सम्मान करने हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के पक्ष में है। उनके अनुसार,

अवामी लीग के नेता बांग्लादेश लौटकर सामान्य राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हिरासत में बंद नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी राहत मिलती है तथा राजकीय प्रतिबंध हटाए जाते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी गतिविधियाँ संचालित करने का अवसर मिलना चाहिए। अवामी लीग का कहना है कि वह बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहकर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहती है और इसके लिए आवश्यक संवैधानिक और कानूनी वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हालाँकि, इन दावों और मांगों पर

बांग्लादेश सरकार अथवा संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया है, यह

स्पष्ट होना अभी बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अवामी लीग के नेताओं की संभावित वापसी

और उनकी ओर से उठाई गई मांगें आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती

हैं। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे की कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे

बढ़ती है तथा शेख हसीना और उनके सहयोगियों की प्रस्तावित वापसी को लेकर क्या निर्णय सामने आते हैं।



અમદાવાદ
મ્યુનિસિપલ
કોર્પોરેશન






અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન,
ઓડા તથા માર્ગ અને મકાન વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે
ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તાર અને
અમદાવાદ પૂર્વ અને પશ્ચિમ લોકસભા વિસ્તારનાં
અંદાજિત **₹૪૦૫** કરોડના ખર્ચે
કુલ **૨૯** પ્રજાલક્ષી કાર્યોનું




શ્રી અમિતભાઈ શાહ
માનનીય સંસદસભ્ય ગાંધીનગર લોકસભા અને
ગૃહ તથા સહકાર મંત્રી, ભારત સરકારના વરદ્હસ્તે
માનનીય મુખ્યમંત્રી
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ
ઉપસ્થિતિમાં




વૃક્ષારોપણ, લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત

૧૨-૦૭-૨૦૨૬, રવિવાર ♦ સવારે ૮:૩૦ વાગે

જાહેર સભા સ્થળ: વિજ્ઞાન ભવન, સાયન્સ સિટી, સોલા, અમદાવાદ

શહેરીજનોએ
ગેટ નં. 6 થી
પ્રવેશ મેળવવાનો
રહેશે.

₹૩૦૫ કરોડના ૨૨ પ્રજાલક્ષી કાર્યોનું

લોકાર્પણ

- ₹૮૨ કરોડની એસી ઇલેક્ટ્રિક બસો
- ₹૬૫ કરોડના રોડ પ્રોજેક્ટ
- ₹૬૫ કરોડના વોટર પ્રોજેક્ટ
- ₹૬૧ કરોડના હાઉસીંગ પ્રોજેક્ટ
- ₹૧૮ કરોડના બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ
- ₹૧૧ કરોડના ગાર્ડન અને તળાવ પ્રોજેક્ટ
- ₹૩ કરોડના અન્ય વિકાસના કામો

₹૧૦૦ કરોડના ૭ પ્રજાલક્ષી કાર્યોનું

ખાતમુહૂર્ત

- ₹૪૭ કરોડના હાઉસીંગ પ્રોજેક્ટ
- ₹૪૨ કરોડના બીઆરટીએસ પ્રોજેક્ટ
- ₹૬ કરોડના ગાર્ડન અને તળાવ પ્રોજેક્ટ
- ₹૨ કરોડના બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ

એક ઐતિહાસિક દિવસ
101 ઓડિસેજન પાર્ક
લોકાર્પણ એક જ દિવસે





એસી ઇલેક્ટ્રિક બસો (AMTS)



આવાસો, રાણીપ



એસી ઇલેક્ટ્રિક બસો (BRTS)



વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટેશન, તોલાવ



કમ્પ્યુનિટી હોલ, ચાંદલોડિયા



સ્ટોર્મ વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન, નિકોલ



અંડરપાસ, ઓગણજ



હેરિટેજ પાર્ક, એલિસાબિજ

**મિશન ફાઈવ મિલયન ટ્રીઝ અંતર્ગત
સામૂહિક વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ**

સમય: સવારે ૯.૩૦ વાગે

સ્થળ: થલતેજ વૉર્ડમાં ટીપી ૩૦૧, એફપી ૨૫૫, ૨૪૬, ગોતા ગોધાવી કેનાલ પાસે, ભાડજ, અમદાવાદ



સમય: સવારે ૧૦.૦૦ વાગે

સ્થળ: ટીપી ૨૦૪, એફપી ૩૪૭ + ૪૨૪, સવજાહ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, સરખેજ, અમદાવાદ



સમય: સવારે ૧૦.૪૫ વાગે

સ્થળ: NDDB પ્લોટ, વાડજ BRTSની સામે, કાર્ગો મોટરથી કિ-માર્ટ રોડ પર, વાડજ, અમદાવાદ



વધુ હરિયાળી ♦ વધુ પ્રાણવાયુ ♦ વધુ સ્વસ્થ અમદાવાદ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન

મહાનગર સેવા સંદન, સરદાર પટેલ ભવન, દાશાપીઠ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧

www.ahmedabadcity.gov.in | /AhmedabadAMC | @AmdavadAMC | @AhmedabadAMC

गुजरात की उपलब्धियों में जुड़ा एक और मोर पंख : बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गुजरात को मिला सम्मान

► नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में गुजरात को प्रतिष्ठित 'एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026' से सम्मानित किया गया

► केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के करकमलों से अवॉर्ड प्रदान किया गया, जिसे गुजरात सरकार की ओर से कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने ग्रहण किया

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

► गुजरात को इससे पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में की गई नूतन पहलों के परिणामस्वरूप वर्ष 2009, 2014 और 2018 में 'श्रेष्ठ कृषि राज्य' श्री ई. श्रीनिवास एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश से मूलाकात की। संरक्षा निरीक्षण के दूसरे दिन बेचराजी रेलवे स्टेशन पर विधायक श्री सुखाजी सोमाजी ठाकोर ने रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) श्री ई. श्रीनिवास एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की उपस्थिति में चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कटोसण रोड-राणपुर रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ होने की दिशा में हो रही प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधामंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया। स्थानीय नागरिकों ने विश्वास व्यक्त किया कि रेलवे संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति के उपरांत इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ होने से देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को मौं बहुचराजी मंदिर तक अधिक सुगम, सुरक्षित

बेचराजी के विधायक श्री सुखाजी ठाकोर ने DRM एवं CRS के साथ की बैठक, खारे पानी की समस्या के शीघ्र समाधान का आरवासन,नागरिकों ने जताई खुशी बहुचराजी तक रेल संपर्क के लिए प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री का किया आभार व्यक्त

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत कटोसण रोड-राणपुर रेलखंड पर रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) श्री ई. श्रीनिवास द्वारा किए जा रहे संरक्षा निरीक्षण के दौरान बेचराजी के विधायक श्री सुखाजी सोमाजी ठाकोर ने मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश से मुलाकात की। संरक्षा निरीक्षण के दूसरे दिन बेचराजी रेलवे स्टेशन पर विधायक श्री सुखाजी सोमाजी ठाकोर ने रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) श्री ई. श्रीनिवास एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की उपस्थिति में चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कटोसण रोड-राणपुर रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ होने की दिशा में हो रही प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधामंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया। स्थानीय नागरिकों ने विश्वास व्यक्त किया कि रेलवे संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति के उपरांत इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ होने से देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को मौं बहुचराजी मंदिर तक अधिक सुगम, सुरक्षित

चुड़ा एवं राणपुर रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (AFDAS) का सफल कमीशनिंग

यात्रियों की सुरक्षा एवं रेलवे परिसंपत्तियों की संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने सुरक्षा अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल दूरसंचार एवं सिग्नल इंजीनियर (Sr. DSTE) श्री एच. एस. आर्या के नेतृत्व एवं देखरेख में सुरेन्द्रनगर-बोटाद रेलखंड के चुड़ा एवं राणपुर रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (AFDAS) का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर इसे कमीशन कर दिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत चुड़ा रेलवे स्टेशन पर 07 जुलाई तथा राणपुर रेलवे स्टेशन पर 08 जुलाई को AFDAS प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। यह अत्याधुनिक प्रणाली



आग अथवा धुएँ की प्रारंभिक अवस्था में ही स्वतः पहचान कर तत्काल अलार्म सक्रिय करती है, जिससे समय रहते आवश्यक सुरक्षा एवं बचाव संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। इस आधुनिक प्रणाली में स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, गैस

सेंसर, मैनुअल कॉल प्वाइंट, मॉनिटर मॉड्यूल, इनपुट-आउटपुट मॉड्यूल, लूप साउंडर तथा पावर सप्लाई यूनिट जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। इन उपकरणों के माध्यम से किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना का प्रारंभिक स्तर पर ही पता लगाकर

श्री अमित शाह के हरियाली लोकसभा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अहमदाबाद के निकट गोधावी गांव में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा गुजरात का सबसे बड़ा ‘महा वन कवच’

►► **मियावाकी से एक कदम आगे : गुजरात का ‘वन कवच’ मॉडल श्री अमित शाह के ‘हरियाली लोकसभा’ विजन को देगा गति**

►► **इस वर्ष वन विभाग द्वारा ‘वन कवच’ मॉडल के तहत पूरे राज्य में 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में किए जाने वाले वृक्षारोपण में से 600 हेक्टेयर में बनने वाले ‘वन कवच’ केवल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ही विकसित किए जा रहे हैं**

►► **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ के जरिए वृक्षारोपण क्षेत्र में हो रही है क्रांति**

►► **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नेतृत्व में गुजरात को और हरा-भरा बनाने के लिए वन महोत्सव जैसे विशेष अभियानों के जरिए चलाई जा रही है मुहिम**

►► **केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह स्थानीय जलवायु के अनुकूल स्वदेशी वनस्पति प्रजातियों को दे रहे हैं प्रोत्साहन**

गांधीनगर : जाने-माने गुजराती कवि जीनाभाई देसाई ‘स्नेह रश्मि’ ने जापानी काव्य शैली ‘हाइकु’ को गुजराती साहित्य में प्रस्तुत किया, जो एक तीन पंक्तियों और सत्रह अक्षरों के एक विशिष्ट प्रारूप का अनुसरण करती है। इसके ठीक छह दशक बाद, गुजरात ने एक बार फिर वृक्षारोपण की जापानी पद्धति ‘मियावाकी वन वृक्षारोपण’ मॉडल को कुछ अलग और स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप मौलिक स्वरूप में ‘वन कवच’ के रूप में अपनाया है।

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में महत्वाकांक्षी ‘गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान’ की शुरुआत की है। इस अभियान के हिस्से के रूप में, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इनमें से लगभग 60 लाख पौधे वन विभाग द्वारा अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में ‘वन कवच’ मॉडल का उपयोग करके लगाए जाएंगे। गुजरात का यह मॉडल जापानी मियावाकी मॉडल का एक गुजराती रूप है। विशेष रूप से स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया यह मॉडल वैज्ञानिक तरीके से भूमि सुधार और जैव विविधता संरक्षण को जोड़कर खराब हो चुकी जमीन को स्वयं से विकसित होने वाले देसी पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में बदलने का प्रयास करता है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के जरिए वृक्षारोपण क्षेत्र में एक क्रांति हो रही है। गुजरात को और अधिक हरा-भरा बनाने के लिए वन महोत्सव जैसे विशेष अभियानों के माध्यम से एक मुहिम शुरू की गई है।



वन कवच की सफलता के बाद बढ़ा दायरा

गुजरात के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने कहा, “श्री अमित शाह के गांधीनगर हरियाली लोकसभा प्रोजेक्ट के अंतर्गत अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में 600 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 82 ‘वन कवच’ विकसित किए जाएंगे। इनमें से अहमदाबाद के निकट स्थित गोधावी गांव में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में गुजरात का सबसे बड़ा ‘महा वन कवच’ विकसित किया जा रहा है।”

वन विभाग ने 2023 में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण के जरिए ‘वन कवच’ शुरू किया था। इस मॉडल को मिली सफलता के बाद वन विभाग ने वन कवच के तहत 2024-25 के दौरान इसका दायरा बढ़ाकर 200 हेक्टेयर और 2025-26 में 400 हेक्टेयर कर दिया।

2026 तक पूरे राज्य में इस मॉडल के तहत विकसित किया गया कुल क्षेत्र 600 हेक्टेयर तक पहुंच गया है।

गुजरात में वन कवच मॉडल का विस्तार

वन विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने आगे कहा, “वन कवच मॉडल की सफलता के आधार पर, वन विभाग अ 2026-27 के दौरान पूरे गुजरात में 500 नई वन कवच साइटें बनाएगा। इस वर्ष वन कवच पहल के तहत प्रस्तावित 1100 हेक्टेयर क्षेत्र के नए वृक्षारोपण में से आधे से अधिक यानी 600 हेक्टेयर केवल गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही विकसित किए जाएंगे।”

वन कवच बनाम मियावाकी :

गुजरात तेजी से हरित आवरण बढ़ाने के बजाय दीर्घकालिक पारिस्थितिकी को क्यों चुन रहा है ?

मूल मियावाकी पद्धति जापान के

शंकुधारी पेड़ों की बहुतायत वाले जंगलों के लिए विकसित की गई थी, जिसमें प्रति वर्ग मीटर तीन से पांच पौधे लगाए जाते हैं। इस घनी रोपाई से पौधों के बीच सूर्य प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे केवल सबसे मजबूत पेड़ ही जीवित रह पाते हैं और तीन से पांच वर्षों में तेजी से जंगल का विकास होता है। सामान्य मियावाकी पौधारोपण में शुरुआत में प्रति हेक्टेयर करीब 50,000 पौधे हो सकते हैं, जो प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। हालाँकि, वन अधिकारियों के अनुसार, पारिस्थितिकीविदों ने पाया कि जापानी मॉडल का सीधा अनुकरण भारत की देसी वृक्ष प्रजातियों के लिए उचित नहीं हो सकता। हमारे कई स्वदेशी पेड़ों का फैलाव या आवरण (कैनोपी) तथा जुड़े बहुत विशाल होती हैं, जो सीधी और



आड़ी दोनों दिशाओं में फैलती हैं। अत्यंत घनी रोपाई से जड़ों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जो उनके स्वस्थ विकास को सीमित कर देती है और वृक्षारोपण की दीर्घकालिक स्थिरता भी कम हो जाती है।

इन कमियों को दूर करने के लिए, गुजरात वन विभाग ने ‘वन कवच’ मॉडल विकसित किया है, जो प्राकृतिक रूप से जंगल के पनपने के पारिस्थितिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए पेड़ों के बीच अधिक दूरी रखता है। इस मॉडल में प्रति वर्ग मीटर लगभग एक पेड़ लगाया जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि बड़े फैलाव (आवरण) वाली प्रजातियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी हो। यह अतिरिक्त जगह पेड़ों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश, नमी और पोषक तत्व हासिल करने में मदद करती है, जिससे वे प्राकृतिक रूप से बहुस्तरीय जंगलों में बदल सकते हैं।

वन कवच मियावाकी पद्धति से इस प्रकार अलग है

अधिकारियों के अनुसार, यह मॉडल

जमीन यानी मिट्टी की तैयारी में भी उल्लेखनीय रूप से अलग है। मियावाकी तकनीक के विपरीत, जिसमें अक्सर पूरी जगह की मिट्टी बदलनी पड़ती है, वन कवच केवल पौधे लगाने के गड्ढों को ही प्रभावित करता है और मिट्टी की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखता है। प्रति हेक्टेयर लगभग 10,000 गड्ढे तैयार किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न देसी प्रजातियों का समावेश करने के लिए छोटे और बड़े दोनों प्रकार के गड्ढे बनाए जाते हैं। इससे पेड़ों की जड़ें बिना छेड़ी गई मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं, जो उन्हें मजबूत पकड़ देती है। गुजरात में यह एक महत्वपूर्ण फायदा है, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात और तेज हवाओं की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वनकवच की एक और खासियत यह है कि यह केवल पेड़ों की संख्या बढ़ाने के बजाय प्राकृतिक जंगल की संरचना को फिर से बनाने पर जोर देता है। पौधरोपण को ऊपरी स्तर (अपर कैनोपी), मध्यम स्तर और निचले स्तर की प्रजातियों के साथ डिज़ाइन किया गया

है, जो प्राकृतिक जंगलों की रचना के साथ काफी हद तक मिलती-जुलती है। यह अलग-अलग स्तरों वाली वनस्पति वन्यजीवों के आश्रय स्थान की विविधता में सुधार करती है और पक्षियों, तितलियों, परागण करने वाले कीड़ों, सरीसृपों और स्तनधारी प्राणियों सहित मिट्टी के अनगिनत सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती हैं।

वन कवच मॉडल स्वदेशी जैव विविधता पर जोर देता है

यह पहल स्वदेशी जैव विविधता पर विशेष जोर देती है। तेजी से विकसित होने वाली सीमित वनस्पति प्रजातियों पर निर्भर रहने के बजाय, वन विभाग ऐसे स्थानीय पेड़ लगा रहा है, जो हजारों वर्षों से गुजरात के वन्यजीवों के साथ विकसित हुए हैं। ये प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से स्थानीय जलवायु की परिस्थितियों के अनुकूल हैं, उन्हें बाहर से कम ख़ाद या देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अपेक्षा है कि समय के साथ-साथ वे स्वयं से विकसित होने वाले जंगल पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित हो जाएंगी। वन अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन्यजीवों के आश्रयस्थान में सुधार करना, खराब जमीन को ठीक करना, कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ाना, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना, नमी बनाए रखना और पूरे क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने की क्षमता (क्लाइमेट रेजिलिएन्स) को मजबूत करना है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत के भटार में बाढ़ प्रभावितों को कैश डोलर्स सहित सहायता का वितरण किया

►► **भटार के आंबेडकरनगर, आजादनगर, इंदिरानगर तथा रसूलाबाद क्षेत्रों के 2000 परिवारों को आर्थिक सहायता का भुगतान**

►► **भारी वर्षा के बाद पानी उतरते ही सूरत जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू**

►► **जिला कलेक्टर व मनपा आयुक्त की उपस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कर हाथों-हाथ सहायता वितरण**

►► **पुनर्वास एवं सामान्य जीवन की ओर लौटने की समग्र यात्रा में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी : उप मुख्यमंत्री**

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत में भारी वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित भटार के आंबेडकरनगर, आजादनगर, इंदिरानगर और रसूलाबाद के दो हजार प्रभावित परिवारों को शुक्रावर को कैश डोलर्स, घरेलू सामान, कपड़ा सहायता सहित प्रति परिवार 6800 रुपए की आर्थिक सहायता का वितरण किया।

श्री संघवी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और प्रशासन द्वारा किए जा रहे ‘डोर-टू-डोर’ सर्वेक्षण में पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित

नहीं रहेगा और हर घर जाकर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्षा से प्रभावित सूरत ने फिर एक बार अपने अदम्य साहस, धीरज तथा एकता को परिचय दिया है। मुश्किल परिस्थितियाँ होने के बावजूद लोगों ने हिमत नहीं हारी है और वे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक-दूसरे का सहारा बनकर साथ खड़े रहे हैं। जिन परिवारों, व्यापारियों तथा नागरिकों को माल-सामान नुकसान हुआ है तथा उनकी आजीविका प्रभावित हुई है, ऐसे हर परिवार के लिए 6800 रुपए की सहायता आर्थिक संशल बनेगी।



उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हर मुश्किल स्थिति में प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने जोड़ा कि यह आर्थिक सहयोग केवल आज तक के लिए सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुनर्वास एवं सामान्य जीवन की ओर लौटने की समग्र यात्रा में सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।

सूरत में मूसलाधार वर्षा के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर श्री तेजस परमार ने तत्काल सर्वेक्षण शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत प्रांत अधिकारी (दक्षिण)

श्री वी. जे. भंडारी के मार्गदर्शन में मजूरा क्षेत्र के प्रभावितों का सर्वेक्षण कर उन्हें घरेलू सामान तथा मनरेगा योजनानुसार दैनिक मेहनताना सहित 6800 रुपए की सहायता वितरित करने की कार्यवाही शुरू की गई। श्री भंडारी के मार्गदर्शन में सूरत शहर में अब तक अनुमानित 2500 से अधिक परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान की गई है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री तेजस परमार, मनपा आयुक्त श्री एम. नगराजन, प्रांत अधिकारी (दक्षिण) श्री वी. जे. भंडारी सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी राहत-बचाव-सहायता कार्य में सहभागी हुए।

गुजरात की उपलब्धियों में जुड़ा एक और मोर पंख : बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गुजरात को मिला सम्मान

►► **नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में गुजरात को प्रतिष्ठित ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026’ से सम्मानित किया गया**

►► **केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के करकमलों से अवॉर्ड प्रदान किया गया, जिसे गुजरात सरकार की ओर से कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने ग्रहण किया**

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

►► गुजरात को इससे पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में की गई नूतन पहलों के परिणामस्वरूप वर्ष 2009, 2014 और 2018 में ‘श्रेष्ठ कृषि राज्य’ का अवॉर्ड प्राप्त हो चुका है

►► वर्ष 2008 में महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. स्वामीनाथन के मार्गदर्शन में प्रतिष्ठित ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ की शुरुआत हुई थी

►► राष्ट्रीय सम्मान राज्य के परिश्रमी किसानों और कृषि विभाग के कर्मयोगियों को समर्पित है

गांधीनगर : हाल ही में गुजरात की उपलब्धियों में एक और मोर पंख जुड़ा है। नई दिल्ली में आयोजित ‘17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव- 2026’ अंतर्गत आयोजित प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में गुजरात को बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026’ से सम्मानित किया गया।

इस समारोह में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाउ किसनराव बागड़े

के करकमलों से यह अवॉर्ड प्रदान किया गया। गुजरात की ओर से यह सम्मान कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने ग्रहण किया।

उल्लेखनीय है कि भारत के कृषि क्षेत्र में नीति-निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में शुरू हुआ ‘एग्रीकल्चर टुडे’ गुप्त देश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रभावशाली मंच बन चुका है। वर्ष 2008 में महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. स्वामीनाथन के



मार्गदर्शन में इस समूह द्वारा ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ की शुरुआत की गई थी, जिसका 17वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस पुरस्कार की मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. सदाशिवम हैं, जो इसकी पारदर्शिता व गरिमा को दर्शाता है।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात को वर्ष 2009 और 2014 में ‘श्रेष्ठ कृषि राज्य’ के रूप में ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ प्राप्त हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि महोत्सव, सांथल

गुजरात के लाखों परिश्रमी किसानों और कृषि विभाग की पूरी टीम का है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को गुजरात के अन्नदाताओं को समर्पित करते हुए राज्य के सभी किसानों, बागवानी क्षेत्र से जुड़े कर्मयोगियों तथा कृषि विभाग की पूरी टीम को शुभकामनाएँ दीं।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात को वर्ष 2009 और 2014 में ‘श्रेष्ठ कृषि राज्य’ के रूप में ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ प्राप्त हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि महोत्सव, सांथल

हेल्थ कार्ड और टपक सिंचाई जैसी नूतन पहलों के माध्यम से 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सर्वाधिक 9.9 प्रतिशत की ऐतिहासिक कृषि विकास दर हासिल की थी।

उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद वर्ष 2018 में भी गुजरात को ‘श्रेष्ठ कृषि राज्य’ के रूप में तथा वर्ष 2019 में पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया था। अब सात वर्ष बाद एक बार फिर गुजरात को बागवानी क्षेत्र के लिए यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड प्राप्त हुआ है। श्री वाघाणी ने जोड़ा कि यह अवॉर्ड राज्य के लिए केवल गर्व का विषय ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ हासिल करने की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।

इस गौरवपूर्ण समारोह में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाउ किसनराव बागड़े, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही तथा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं ज्यूरि अध्यक्ष जस्टिस पी. सदाशिवम सहित अनेक वरिष्ठ महानुभावों ने गुजरात की मॉडल कृषि नीतियों की मुक्तकंठ से सराहना की तथा यह पुरस्कार प्राप्त करने पर गुजरात सरकार और राज्य के किसानों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

►► **नई मनपाओं की सीमा में शामिल किए गए क्षेत्रों और ‘ट्रांजिशन फेज’ को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुविधाओं से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए अगले पांच वर्षों तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी**

►► **मेहसाणा, नडियाद, आणंद, नवसारी, वापी, मोरबी, गांधीधाम, सुरेन्द्रनगर और पोरबंदर महानगर पालिकाओं को मिलेगा लाभ**

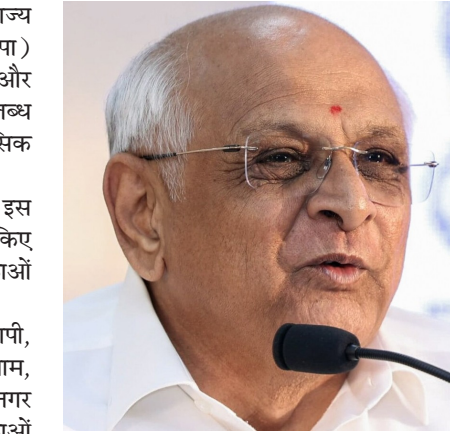
गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नवगठित नौ महानगर पालिकाओं (मनपा) को मजबूत बनाकर नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य की नगर पालिकाओं को इस प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए पहले किए गए निर्णय में अब इन 9 महानगर पालिकाओं का भी समावेश किया गया है।

इस निर्णय के अनुसार राज्य की वापी, मेहसाणा, पोरबंदर, मोरबी, गांधीधाम, नडियाद, आणंद, नवसारी और सुरेन्द्रनगर सहित कुल 9 नवगठित महानगर पालिकाओं को अगले पांच वर्षों तक सार्वजनिक हित से जुड़ी 11 विभिन्न आवश्यक नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

श्रेणी की नगर पालिकाएं थीं, जिन्हें अपग्रेड करके महानगर पालिका का दर्जा दिया गया है और अभी इनका ‘ट्रांजिशन फेज’ यानी बदलाव का दौर चल रहा है। इतना ही नहीं, इन नई महानगर पालिकाओं की सीमा में भी एक बड़ा क्षेत्र शामिल किया गया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया को और आसान बनाने का दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि नई महानगर पालिकाओं में सर्वांगीण विकास के कार्य तेजी से हो सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नई महानगर पालिकाओं को नागरिक सुविधा के जिन



11 महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, उसमें नगर सेवा सदन (मनपा का कार्यालय भवन), फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी), भूमिगत गटर ड्रेनेज, पंपिंग स्टेशन, जलपूर्ति प्रोजेक्ट (जलापूर्ति के कार्य), सॉलिड/लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, स्टॉम वाटर ड्रेनेज का कार्य (बरसाती पानी की निकासी के लिए), बालवाड़ी (आंगनवाड़ी) और टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल और कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के इस दूरगामी निर्णय के परिणामस्वरूप नई महानगर पालिकाओं के क्षेत्रों में फायर स्टेशन, एसटीपी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सार्वजनिक उद्यान जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से निर्माण हो सकेगा तथा शहरी विकास के कार्यों में भी नई गति आएगी।